रविवारीय

क्या विश्व के प्रेसिडेंट हो गए हैं डोनाल्ड ट्रंप?

राजीव खंडेलवाल
(लेखक वरिष्ठ कर सलाहकार एवं पूर्व सुधार न्यास अध्यक्ष हैं)

विश्व राजनीति इस समय ऐसे मोड़ पर खड़ी है, जहाँ यह प्रश्न उठना स्वाभाविक है, क्या विश्व अब संस्थाओंसे नहीं, व्यक्ति''(ट्रम्प) से संचालित होगा? क्या वर्ष 1945 में द्वितीय विश्वयुद्ध की राख से जन्मी वैश्विक व्यवस्था संयुक्त राष्ट्र संघ अब वही आसमानी वही सुल्तानीएकध्रुवीय शक्ति (अमेरिका) के सामने नतमस्तक हो चुकी है?

28 फरवरी 2026 को अमेरिका ने इजराइल के साथ मिलकर ईरान के परमाणु स्थलों-फोर्डो, नतांज और इस्फाहान पर हमला किया. इस पूर्व-निवारकहमले को अमेरिका व उसके सहयोगियों की सुरक्षा के लिए आवश्यक बतलाया गया. अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्प ने दावा किया कि ईरान की परमाणु सुविधाएँ पूरी तरह नष्ट कर दी गई हैं. छुद नदी भरि चलि उतराई''. तथापि यही दावा जून 2025 के हमले के समय में भी अमेरिका ने किया था.

अमेरिकी विदेश मंत्री मार्को रूबीओ का बयान बचकाना व चौंकाने वाला है. हमले के दूसरे दिन अर्थात 1 मार्च को कहा कि रूबीओ ने इजराइल की ईरान पर हमले की योजना के कारण ईरान की संभावित प्रतिक्रिया जो अमेरिकी पर हमले के रूप में हो सकती थी, से बचने के लिए यह हमले की कार्रवाई की गई. यानी पहले युद्ध करो, बाद में कारण ढूंढो क्या यही नई वैश्विक नीतिहै?

सबसे दुखद व गंभीर तथ्य यह है कि ऐसे समय यह हमला हुआ, जब ओमान के विदेश मंत्री की मध्यस्थता में ईरान और अमेरिका के बीच परमाणु कार्यक्रम के शांतिपूर्ण उपयोग को लेकर वार्ता न केवल अंतिम चरण में थी, बल्कि उसमें कुछ सफलताएं भी मिल रही थी. पीठ पर छुरा मार कररणभूमि में बम गिर रहे थे. इसे कहते हैं- हाथ में जैतून की डाली और पीठ पीछे तलवार. इस हमले में ईरान के सर्वोच्च धार्मिक नेता अयातुल्लाह अली खोमेनेईसहित कई शीर्ष सैन्य कमांडर (लगभग 32) मारे गये.

193 सदस्य देशों का अंतरराष्ट्रीय संगठन संयुक्त राष्ट्र संघका उद्देश्य विश्व शांति, सुरक्षा और मैत्री-सद्भाव बनाए रखने के साथ यू एन चैप्टरका उल्लंघन करने पर विभिन्न प्रतिबंधों को लगाने का कार्य भी है. सुरक्षा परिषद यूएनओ की सबसे प्रभावशाली इकाई है. परंतु प्रश्न आज यह उठता है, क्या यह संस्था केवल कागजी शेरबनकर रह गई है? महासचिव एंटोनियो गुटेर्रेस की आवाज, उपस्थिति इस संकट में कितनी प्रभावी रही? ईरान परमाणु हथियार बनाने की क्षमता तक पहुंचा है या नहीं? यह निर्णय क्या संयुक्त राष्ट्र संघ या अंतरराष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेंसी का नहीं होना चाहिए था कि जब वैश्विक संस्थाएं मौन हो जाएं, तो शक्तिशाली राष्ट्र न्यायाधीश, जूरी और जल्लाद तीनों की भूमिका निभाने लगते हैं.

तुम ही कातिल, तुम ही मुद्दई, तुम ही मुंसिफके प्रतीक वैश्विक तानाशाह अमेरिका यह रवैया नया नहीं है. 'पागल', 'सनकी' ट्रम्प ने अमेरिकन कांग्रेस की स्वीकृति लिए बिना हिटलर व मुसोलनी की तरह अंतरराष्ट्रीय कानून की धज्जियाँ उड़ाते हुए आग में घीडालकर विश्व को तृतीय विश्वयुद्ध के मुहानेपर लाकर खड़ा कर दिया. इतिहास गवाह है:-

- 1983 ग्रेनेडा पर तत्कालीन सरकार को उखाड़ फेंकने के लिए आक्रमण.
- 1989 पनामा पर ऑपरेशन जस्ट कॉज मैनुअल नोरियागा को हटाने के लिए.

- 1999 कोसोवो में नाटो बमबारी.
- 2001 अफगानिस्तान पर हमला.
- 2003 रासायनिक हथियारों का झूठा आरोप लगाकर, सद्दाम हुसैन के शासन को उखाड़ फेकने के लिए ऑपरेशन इराकी फ्रीडम.
- 2011 लीबिया में मुअम्मर गद्दाफी के खिलाफ सैन्य हस्तक्षेप.
- विश्व की भयंकर आतंकवादी 9/11 घटना के बाद पाकिस्तान के एबटाबाद में ओसामा बिन लादेन को ऑपरेशन नेप्च्यून स्पीयर के तहत मार गिराया गया.
- 2020 ईरान के जनरल कासिम सुलेमानी की हत्या.
- 22 जून 2025 को ईरान पर हमला करके दावा किया गया कि ईरान के परमाणु कार्यक्रम नष्ट कर दिया गया. इस दावे के बावजूद फिर उसी उद्देश्य को लेकर आज हमला जारी है.
- 3 जनवरी 2026 को सैन्य अभियान के तहत वेनेजुएला के राष्ट्रपति निकोलस मादुरो को उठाकर कैद करने की कार्रवाई.

अधिकांश कार्रवाइयाँ यूएनएसकि की स्पष्ट अनुमति के बिना हुईं. हर बार तर्क दिया गया. आत्मरक्षा या मानवीय संकट. वाह! तुम कत्ल करो हो की करामात करो हो.

जब कोई ताकतवर राष्ट्र का प्रमुख यह तय करने लगे कि कौन-सा देश परमाणु शक्ति बने और कौन नहीं; कौन-सा शासन वैध है और कौन नहीं; किसे जीवित रहना है, किसे हटाया जाना है और किसकी छाती पर सवार होना है, तो स्वाभाविक है कि यह प्रश्न उठेगा, क्या वह तानाशाह व्यक्ति स्वयं को विश्व का प्रधानसमझ बैठा है?

यह स्थिति वैसी ही है, जैसे किसी समय टेस्ट क्रिकेट में विश्व एकादश बनती थी, जो क्रिकेट खेलने वाले अन्य देशों के साथ खेलती थी. परंतु यहाँ तो एक देश स्वयं को अंपायर भी मान रहा है और खिलाड़ी भी.

अंतरराष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेंसी की विभिन्न रिपोर्टों में यह कहा गया है कि ईरान का कोई अघोषित संरचित परमाणु कार्यक्रम नहीं है. उन्होंने ईरान के परमाणु कार्यक्रम को शांतिपूर्ण बताया, स्वयं ईरान के सर्वोच्च नेता खामेनेई ने कई बार (2005, 10, 12, 19, में) परमाणु हथियारों को इस्लामिक दृष्टि से हराम (निषेध) बताया था. यदि खुफिया एजेंसियों और अंतरराष्ट्रीय निगरानी संस्थाओं व हाथ कंगन को आरसी क्या, स्वयं अमेरिका की सीआईए की रिपोर्टें यह कहती हैं कि, ईरान ने परमाणु बम नहीं बनाया है. एक नजीर सो दलीलों से बेहतर होती है'', तो फिर युद्ध की घोषणा किस आधार पर?

निष्कर्ष-जिसकी लाठी, उसकी भैंस की नीति, यदि वैश्विक राजनीति का मंत्र बन जाए, तो संयुक्त राष्ट्र संघ जैसी संस्थाएँ कागजी होकर महज औपचारिक मंच बनकर रह जाएँगी. प्रश्न यह नहीं कि ईरान सही है या अमेरिका; बल्कि क्या विश्व में निर्णय अंतरराष्ट्रीय संबंधित संस्थाएं लेंगी या अनाधिकृत स्वयंभू विश्व गुरु व्यक्ति? ऐसी स्थिति में इतिहास लिखेगा 21वीं सदी में व्यक्ति ने व्यवस्था को, शक्ति ने तंत्र को परास्त कर दिया. और तब सचमुच पूछा जाएगा, या क्या डोनाल्ड ट्रंप केवल अमेरिका के राष्ट्रपति थे, या विश्व के भी?

भारत का दृष्टिकोण संयम या ट्रंप के दबाव में?

भारत ने आतंकवाद के गंभीर घाव सहे हैं. 26/11 मुंबई हमलों के दोषियों में लश्कर-ए-तैयबा संस्थापक हाफिज मुहम्मद सईद और जैश-ए-मोहम्मद मसूद संस्थापक अजहर जैसे नाम शामिल रहे हैं. 1993 मुंबई बमकांड के मास्टरमाइंड दाऊद इब्राहिम व टाइगर मेनन का नाम सामने आया. ये सब पाकिस्तान में हैं. बावजूद इसके भारत ने छापामार कारवाईकर उन्हें इस पृथ्वी से अलविदाकरने का कोई प्रयास नहीं किया बावजूद इस तथ्य के कि ऐसी कार्रवाइयों के अमेरिका सहित विश्व के अनेकोनेक उदाहरण भरे पड़े हैं. दादागिरी की नीति न अपनाने वाले भारत ने विश्व के सबसे बड़े दादा को अपना सबसे बड़ा दोस्त बतलाने में गाहे-बगाहे कभी कोई कमी नहीं की. जैसी बहे बयार पीठ पुनि तैसी कीजेकी इसी दबाव के चलते भारत ने न तो ईरान पर अमेरिका-इसराइल हमले की निंदा की, न ही खोमेनई की हत्या पर एक शब्द भी कहा. लेकिन ईरान द्वारा अरब गल्फ देशों पर किये हमले की निंदा जरूर की. शायद इसलिए कि वहां एक करोड़ से ज्यादा भारतीय रहते हैं. भारत सरकार के ध्यान में शायद यह बात नहीं रही कि ईरान का चाबहार पोर्ट भारत को पाकिस्तान से गुजरे बिना अफगानिस्तान और मध्य एशियाई देशों तक सीधी पहुंच प्रदान करता है और ईरान, रूस और यूरोप से जोड़ता है, जिससे व्यापार लागत और समय में 30 प्रतिशत तक की कमी आती है. इसी ईरान से भारत पूर्व में रियायती दर पर रुपयो में तेल की खरीदी करता आया रहा है. वैसे भी पिछले 13 महीनों में जबसे ट्रंप ने दूसरी बार पदभार संभाला है, तब से आज तक प्रधानमंत्री मोदी ने 'ट्रंप' का नाम लेकर उसे एक बार भी स्वयं की या भारत की आलोचना करने से या भारत को मान-मर्दित करने से रोका नहीं, बल्कि माई फ्रेंड' के साथ धन्यवाद के लब्ज ही कहते है. जो समझ से परे है. याद कीजिए! अक्टूबर 2025 में ट्रंप ने कहा था मैं उनका (मोदी का) राजनीतिक कैरियर बर्बाद नहीं करना चाहता''. तब भी पूरे देश में चुप्पी? भारत से 2026 नौसैनिक अभ्यास से लौटते समय ईरानी युद्धपोत के भारत की सीमा से निकलने पर अमेरिकी पनडब्बी द्वारा समुद्र में डुबो दिया गया और उस पर सरकार की चुप्पी एक नया प्रश्न खड़ा कर देती है.

स्वयं निर्माण से राष्ट्र निर्माण तक आज की नारी

राजकुमार बरुआ

यत्र नार्यस्तु पूज्यन्ते रमन्ते तत्र देवता:।
यत्रैतास्तु न पूज्यन्ते सर्वास्तत्राफला: क्रिया:॥

अंतरराष्ट्रीय महिला दिवस 8 मार्च केवल एक तारीख नहीं, बल्कि महिलाओं के संघर्ष, उनकी शक्ति और समाज में उनके योगदान को सम्मान देने का एक वैश्विक उत्सव है. यह दिन उन महिलाओं को समर्पित है जिन्होंने अपने अधिकारों जैसे वोट देने का अधिकार, काम के घंटे कम करना और बेहतर वेतन के साथ समानता का अधिकार देने के लिए दशकों पहले आवाज उठाई थी. यह हमें याद दिलाता है कि आज हम जिस समानता की बात करते हैं, वह एक लंबे संघर्ष का परिणाम है. संघर्ष अभी जारी है, और स्वयं सिद्धा उन सभी चुनौतियों का मानसिक दृढ़ता और सकारात्मक दृष्टिकोण के साथ समाधान खोजकर समाज को मजबूती प्रदान कर रही है.

'नारी केवल एक शक्ति नहीं, बल्कि सृष्टि का आधार है'

हम उस सृष्टि की कल्पना भी नहीं कर सकते जिसमें महिलाएं ना हो. और कहते भी है ना कि हर सफल पुरुष के पीछे एक महिला खड़ी है. महिलाएं इस सृष्टि की प्राण वायु है जिससे इस सृष्टि का दिल धड़क रहा है. नारी हर रूप में ही सम्मान जनक है, प्रेम,करुणा शक्ति और शांति का समंदर है. मकान को घर बनाने के लिए महिला का होना आवश्यक है. इस संसार में महिलाओं को जो शक्ति ईश्वर ने दी है, वहां और किसी के पास नहीं है.

स्वयं सिद्धा

आज वह स्वयं सिद्धा है - अर्थात वह जिसने अपनी सिद्धियां स्वयं प्राप्त की हैं और जो अपनी नियति का लेखन अपने साहस और परिश्रम की स्याही से कर रही है. कल तक महिलाओं को घर की चारदीवारी और सामाजिक मर्यादाओं के घेरे में देखा जाता था. आज वह घेरा टूट चुका है. शिक्षा की लौ ने उसे वह दृष्टि दी है, जिससे उसने न केवल अपने अधिकारों को पहचाना है, बल्कि अपनी क्षमताओं का लोहा भी मनवाया है. चाहे वह कॉर्पोरेट जगत की ऊंची इमारतें हों, सीमाओं की सुरक्षा हो, या अंतरिक्ष के अनसुलझे रहस्य—आज ऐसी कोई दहलीज नहीं जिसे स्त्री के कदमों ने ना नापा हो. आज की महिलाओं की सबसे बड़ी विशेषता उसका संतुलन है. वह एक तरफ आधुनिकता के शिखर को छू रही है, तो दूसरी तरफ अपनी जड़ों और संस्कारों को भी संजोए हुए है. वह 'मल्टीटास्किंग' की जीवंत मिसाल है. घर की जिम्मेदारियों को निभाते हुए करियर की ऊंचाइयों पर पहुंचना उसकी अदम्य इच्छाशक्ति का प्रमाण है. वह अब दूसरों के द्वारा तय किए गए रास्तों पर नहीं चलती, बल्कि अपने रास्ते खुद बनाती है.

राष्ट्र निर्माण में महिलाओं की भागीदारी

महिलाएं केवल सहभागिता नहीं, बल्कि आधारशिला है. वे शिक्षा, स्वास्थ्य, रक्षा, राजनीति, और अर्थव्यवस्था के क्षेत्र में सक्रिय योगदान देकर आत्मनिर्भर भारत का निर्माण कर रही हैं. मिशन शक्ति और अन्य सरकारी नीतियों के माध्यम से वे अब रूढ़ियों को तोड़कर सेना, विज्ञान व उद्यमिता में नई ऊंचाइयों को छू रही हैं. आज की नारी हर उस क्षेत्र में अपने आप को दृढ़ इच्छा शक्ति के साथ साबित और स्थापित कर रही है जिस पर पहले उसका पहुंचना भी असंभव माना जाता था. आज महिलाओं ने हर क्षेत्र में अपना योगदान देकर राष्ट्र को मजबूती प्रदान की है. आज हर क्षेत्र में महिलाओं का योगदान सराहनीय है और महिलाओं की बढ़ती भागीदारी से स्वयं-अनुशासन स्थापित होता है जो हर क्षेत्र के लिए अति आवश्यक है.

महिला दिवस के अवसर पर - महिलाओं को दिया जाने वाला सबसे अनमोल और बेहतरीन उपहार उन्हें सच्चा सम्मान, समानता और उनके निर्णयों की स्वतंत्रता देना है. पुरुष वर्ग का भी कर्तव्य बनता है कि वह महिलाओं को आगे आकर काम करने की स्वतंत्रता दे, इसके लिए जरूरी है की वहां महिलाओं के काम में उसको सहयोग करें, चाहें वह काम घरेलू हो या व्यवसाय से जुड़ा हुआ, सहयोग देकर उसके अंदर समानता की भावना को प्रबल करें. घर में काम करती महिलाओं के काम में उनकी मदद करें, उन्हें समय दे कि वहां अपने आपको घरों के साथ अन्य कार्य क्षेत्र में भी स्वतंत्र रूप से काम कर सके. आपका दिया यही सहयोग समाज की जड़ों को मजबूत करेगा और राष्ट्र निर्माण के लिए दोनों की साझेदारी ही राष्ट्र को मजबूती प्रदान करेगी.

भगोरिया को राजकीय मान्यता

अस्मिता, विश्वास और विकास का नया संतुलन

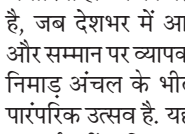

मुकाम सिंह किराड़े

मध्यप्रदेश सरकार द्वारा भगोरिया पर्व को राजकीय गरिमा प्रदान करने का निर्णय केवल एक सांस्कृतिक घोषणा नहीं, बल्कि जनजातीय अस्मिता को मुख्यधारा में सम्मानपूर्वक स्थापित करने की राजनीतिक और सामाजिक पहल है. मुख्यमंत्री मोहन यादव द्वारा बड़वानी के जुलवानिया भगोरिया हाट में की गई यह घोषणा ऐसे समय में आई है, जब देशभर में आदिवासी पहचान, सहभागिता और सम्मान पर व्यापक विमर्श चल रहा है. भगोरिया, निमाड़ अंचल के भील और भिलाला समुदाय का पारंपरिक उत्सव है. यह केवल रंगों, नृत्य और उल्लास का पर्व नहीं, बल्कि सामूहिक जीवन, प्रकृति के साथ संतुलन और सामाजिक समरसता का जीवंत प्रतीक है. मांदल की थाप पर कदम मिलाते महिला-पुरुष, पारंपरिक वेशभूषा और सामुदायिक सहभागिता—ये सब मिलकर इस पर्व को एक सांस्कृतिक अभिव्यक्ति से अधिक, सामाजिक ऊर्जा का उत्सव बनाते हैं. इसे राजकीय मान्यता देना इस सांस्कृतिक पूंजी को स्वीकार करना है, जिसे लंबे समय तक 'स्थानीय' या 'परंपरागत' कहकर सीमित कर दिया गया था.

भारतीय राजनीति में प्रतीकों का अपना महत्व होता है. किसी लोकपर्व को राजकीय दर्जा देना एक संदेश है—यह बताने का कि राज्य अपनी विविधता को औपचारिक पहचान दे रहा है. पिछले वर्षों में प्रधानमंत्री **नरेंद्र मोदी*के नेतृत्व में राष्ट्रीय स्तर पर जनजातीय नायकों और परंपराओं को मुख्यधारा में लाने के प्रयास हुए हैं. मध्यप्रदेश का यह निर्णय उसी व्यापक परिप्रेक्ष्य का प्रादेशिक विस्तार माना जा सकता है.

फिर भी, किसी भी प्रतीकात्मक पहल की वास्तविक सफलता उसके व्यावहारिक परिणामों से तय होती है. यदि सांस्कृतिक सम्मान केवल उत्सव तक सीमित रह जाए, तो उसका प्रभाव क्षणिक हो सकता है. किंतु यदि इसे शिक्षा, कृषि, सिंचाई, बाज़ार पहुंच, उद्यमिता और आधारभूत संरचना से जोड़ा जाए, तो यह दीर्घकालिक परिवर्तन का आधार बन सकता है.इसी संदर्भ में बड़वानी में घोषित विकास योजनाएं महत्वपूर्ण हैं. आधुनिक सब्जी मंडी, 50 एकड़ में आदर्श बीज उत्पादन केंद्र, माइक्रो सिंचाई परियोजनाएं, कोल्ड स्टोरेज और फूड प्रोसेसिंग इकाइयों की स्थापना—ये सभी पहलें दर्शाती हैं कि सरकार सांस्कृतिक सम्मान को आर्थिक सशक्तिकरण से जोड़ना चाहती है. निमाड़ क्षेत्र पहले ही उद्यानिकी और विविध कृषि उत्पादन के लिए जाना जाता है. यदि घोषित योजनाएं प्रभावी रूप से लागू होती हैं, तो यह क्षेत्र मूल्य संवर्धन और कृषि-आधारित उद्योगों के माध्यम से किसानों की आय में वास्तविक वृद्धि कर सकता है. यहां मूल प्रश्न यह है कि क्या यह पहल प्रतीक से नीति तक का सफल संक्रमण कर पाएगी? जनजातीय क्षेत्रों में अभी भी गुणवत्तापूर्ण शिक्षा, स्वास्थ्य सेवाओं और बाज़ार तक पहुंच जैसी चुनौतियां मौजूद हैं. यदि सांस्कृतिक अस्मिता के सम्मान के साथ-साथ इन बुनियादी क्षेत्रों में स्थायी सुधार होते हैं, तभी यह निर्णय ऐतिहासिक महत्व प्राप्त करेगा.

(लेखक पूर्व विधायक है)

बदलते खेल और लोकतंत्र का भरोसा

श्याम यादव

महाराष्ट्र में कुछ समय पहले जो राजनीतिक घटनाक्रम देखने को मिला था, उसकी गूंज अब बिहार की राजनीति में भी सुनाई देने लगी है. देश में सबसे लंबे समय तक मुख्यमंत्री रहने का रिकॉर्ड अपने नाम करने वाले नीतीश कुमार के राज्यसभा जाने की चर्चा ने अचानक नए सवाल खड़े कर दिए हैं. अगर वे सचमुच पटना की कुर्सी छोड़ते हैं, तो बिहार में सत्ता का नया समीकरण बन सकता है. ऐसी स्थिति में पहली बार यह संभावना भी सामने आ रही है कि भारतीय जनता पार्टी राज्य में अपना मुख्यमंत्री बनाने की स्थिति में आ सकती है. फिलहाल यह सब अटकलों और राजनीतिक चर्चाओं के दायरे में है. लेकिन भारतीय राजनीति का अनुभव बताता है कि कई बार ऐसी चर्चाएं ही आगे चलकर वास्तविक घटनाओं का रूप ले लेती हैं. इसलिए इस पर सवाल उठना स्वाभाविक है. सवाल यह नहीं है कि अगला मुख्यमंत्री कौन होगा. राजनीति में चेहरे बदलना कोई असाधारण बात नहीं है. असली सवाल यह है कि चुनाव के समय मतदाताओं के सामने जो तस्वीर रखी जाती है, वह चुनाव के बाद कितनी बदली हुई दिखाई देती है.

नीतीश कुमार का राजनीतिक सफर खुद कई मोड़ों से गुजरता रहा है. वे उन नेताओं में रहे हैं जिन्होंने अलग-अलग समय पर अलग-अलग राजनीतिक साझेदारों के साथ सरकार चलाई है. कभी राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन के साथ, कभी महागठबंधन के साथ और फिर वापस पुराने सहयोगियों के साथ. बिहार की राजनीति पिछले डेढ़ दशक से अधिक समय से इसी तरह के उतार-चढ़ाव की गवाह रही है. इसलिए उनके किसी नए राजनीतिक फैसले पर अब लोगों की हैरानी पहले जैसी नहीं रह गई है.

लेकिन इस बार सवाल केवल किसी एक नेता के फैसले का नहीं है. सवाल उस भरोसे का भी है जो मतदाता अपने वोट के साथ जोड़ता है. पिछले विधानसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी ने नीतीश कुमार के नेतृत्व में ही चुनाव लड़ा था. प्रचार से लेकर राजनीतिक संदेश तक, हर जगह यह स्पष्ट था कि गठबंधन की ओर से मुख्यमंत्री का चेहरा वही हैं. मतदाता जब वोट देने गया, तो उसके सामने यही तस्वीर थी. अब अगर चुनाव के बाद किसी राजनीतिक परिस्थिति में वही चेहरा बदल जाता है और मुख्यमंत्री कोई दूसरा बन जाता है, तो लोगों के मन में सवाल उठना स्वाभाविक है. यह सवाल किसी एक दल या किसी एक राज्य तक सीमित नहीं है. पिछले कुछ वर्षों में देश के कई राज्यों में ऐसी स्थितियां बनी हैं जहां चुनाव से पहले और चुनाव के बाद की राजनीति के बीच साफ अंतर दिखाई दिया.

बिहार में बनती हुई यह नई स्थिति इसलिए भी दिलचस्प है क्योंकि यहां की राजनीति लंबे समय से व्यक्तित्वों के इर्द-गिर्द घूमती रही है. लालू प्रसाद यादव के दौर से लेकर नीतीश कुमार के लंबे राजनीतिक प्रभुत्व तक, राज्य की राजनीति ने कई बड़े मोड़ देखे हैं. ऐसे में अगर सत्ता का नेतृत्व अचानक किसी नए चेहरे के हाथ में जाता है, तो वह केवल एक प्रशासनिक बदलाव नहीं होगा, बल्कि एक राजनीतिक संकेत भी माना जाएगा. हालांकि अभी अंतिम स्थिति सामने नहीं आई है. राजनीति में कई बार आखिरी फैसला आखिरी क्षणों में ही होता है.

राजनीति में सत्ता हासिल करने की कोशिशें नई नहीं हैं. दल अपने हित और परिस्थितियों के अनुसार फैसले लेते हैं. गठबंधन बनते हैं, टूटते हैं और नए समीकरण बनते रहते हैं. यह सब लोकतांत्रिक राजनीति का हिस्सा है. लेकिन लोकतंत्र केवल सत्ता की जोड़-घटाव का खेल नहीं होता. उसकी असली ताकत उस भरोसे में होती है जो मतदाता अपने वोट के जरिए व्यक्त करता है. जब कोई मतदाता मतदान केंद्र तक जाता है, तो वह केवल एक पार्टी या उम्मीदवार को नहीं चुनता. वह उस राजनीतिक दिशा को भी चुनता है जिसकी उम्मीद उसे दिखाई जाती है. अगर चुनाव के बाद वही दिशा बदलती हुई दिखे, तो लोगों के मन में एक असहजता पैदा होना स्वाभाविक है. कई बार यह असहजता खुलकर सामने नहीं आती, लेकिन धीरे-धीरे यह राजनीतिक उदासीनता में बदलने लगती है. बिहार जैसे राज्य में, जहां राजनीति हमेशा से बेहद सक्रिय और बहसों से भरी रही है, वहां यह सवाल और भी महत्वपूर्ण हो जाता है. यहां के मतदाता राजनीति को केवल दूर से देखने वाले दर्शक नहीं हैं. गांव की चौपाल से लेकर शहर की चाय की दुकानों तक राजनीति पर बहस यहां रोजमर्रा की बात है. ऐसे माहौल में अगर बार-बार राजनीतिक तस्वीर अचानक बदलती हुई दिखाई दे, तो लोगों के मन में यह सवाल उठना स्वाभाविक है कि आखिर उनके वोट की असली भूमिका क्या है.

भारतीय जनता पार्टी अक्सर अपनी राजनीति को चाल, चरित्र और चेहरा की कसौटी पर दूसरों से अलग बताती रही है. यह उसका एक राजनीतिक दावा भी रहा है और उसकी पहचान का हिस्सा भी. ऐसे में अगर सत्ता तक पहुंचने के लिए वही तरीके अपनाए जाने लगें जिनकी आलोचना पहले की जाती रही है, तो उस दावे की विश्वसनीयता पर भी सवाल उठ सकते हैं. राजनीति में नैतिक दावों की असली परीक्षा ऐसे ही मौकों पर होती है. यह भी सच है कि भारतीय राजनीति में केवल एक ही दल या एक ही नेता इस तरह की परिस्थितियों से नहीं जुड़ा रहा है. लगभग हर बड़े दल के इतिहास में ऐसे उदाहरण मिल जाते हैं जब चुनावी तस्वीर और बाद की सत्ता संरचना के बीच फर्क दिखाई दिया हो. लेकिन जब ऐसी घटनाएं बार-बार होने लगती हैं, तो उनका असर केवल तत्कालीन सत्ता समीकरण तक सीमित नहीं रहता. वे धीरे-धीरे लोकतांत्रिक व्यवस्था के प्रति लोगों के नजरिए को भी प्रभावित करने लगती हैं.